

①

189

296

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर कैम्प रावा § म०प० §



सम. निग. सीधी नं. १/२०१७/२३०२

- 01 - रामलोकेश नाई तनय जगन्नाथ नाई
- 02 - रामस्वयम्बर नाई तनय जगन्नाथ नाई
- 03 - श्रीमती श्यामकली पत्नी स्व० श्री रामसिया नाई
- 04 - रामानुज नाई तनय स्व० श्री रामसिया नाई
- § 05 § धीरेन्द्र नाई तनय स्व० रामसिया नाई ।
समा निवासी ग्राम मवई, तहसील- चुरहट, जिला - सीधी

§ म०प० § ----- निगरानी कर्ता गण

बनाम

पचोली तनय सुखदेव कोल निवासी ग्राम मवई, तहसील- चुरहट, जिला- सीधी § म०प० § ----- गैर निगरानी कर्ता

आवेदक गण की ओर से श्री अनिलकृष्ण प्रसाद तिवारी द्वारा दावा पत्रा 20-7-17

कलकत्ता कोर्ट राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रावा

निगरानी विरुद्ध आदेशा कलेक्टर महोदय सीधी के प्रकरण नं. माफे 21/अमोल/2001 - 2002 में पारित आदेशा दिनांक 07/12/2009 अन्तर्गत धारा- 170 ख एवं सहायक धारा- 50 भू- राजस्व संहिता 1959ई.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

§ 01 § प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि गैर निगरानी कर्ता ने अनुविभागीय अधिकारी तहसील- चुरहट के न्यायालय में भू- राजस्व संहिता की धारा- 170ख के अन्तर्गत भूमि खरात नम्बर 606 , 606/1 2092, 2092/1 स्थित ग्राम मवई, तहसील- चुरहट के सम्बन्ध में इस आशय का आवेदन-पत्र दिया कि उक्त भूमियों का गैर निगरानी कर्ता भूमिस्वामी है, किन्तु आवेदक जगन्नाथ नाई § मृतक § आधिकृत कब्जा कर रखा है उसे बेदखल कर गैर निगरानी कर्ता से कब्जा वापस दिलाया जाय। विद्वान अनुविभागीय अधिकारी गैर निगरानी कर्ता का आवेदन-पत्र

Handwritten signature

क्र. मसः § 02 §


य
:
ग
हो
मीजाट
य के आदेशा
कर रहे
ध एवं प्रक्रिया
गरानी कर्ता गण
सल्लक्ष क्रिया है
क्रिका की कण्डि
क 27/4/2009
§ नोटीस §
लो कुनिन्दा के
तनय बुद्धान न
पक्षकार बनाने
का उपसमन हो
तर्गत प्रकरण सम
गरानी कर्ता गण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक III / निग0 / भू-रा0 / 2017 / 2302

जिला-सीधी

रामलोचन नाई / पंचोली कोल

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनिरुद्ध सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 21/अपील/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 07.12.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 09.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">  (बी.एम.शर्मा), सदस्य </p>	

AT